



## मुंबई राजधानी का ग्वालियर में स्टॉपेज देने के लिए मुख्यमंत्री ने डीआरएम को लिखा पत्र

ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मुंबई राजधानी का स्टॉपेज ग्वालियर में किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डीआरएम झांसी को पत्र लिखकर ग्वालियर में स्टॉपेज देने की मांग उठाई है। हालांकि इसका प्रस्ताव पहले ही रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है इसलिए सीएम के पत्र को भी बोर्ड को भेज दिया गया है। रेलवे अफसरों की मानें तो यदि केन्द्र और प्रदेश में एक ही राजनीतिक दल की सरकार हो तो इस प्रकार का पत्र काफी प्रभावशाली होता है। लेकिन वर्तमान में केन्द्र और प्रदेश में अलग-अलग दल की सरकार है। ऐसे में इस पर कितनी तवज्जो दी जाती है, यह मंत्रालय पर निर्भर करता है।

मुंबई-दिल्ली राजधानी का संचालन शुरू होने के बाद से लगातार ग्वालियर



### केंद्र में भाजपा प्रदेश में कांग्रेस, पत्र पर क्या रुख लेगा मंत्रालय?

रेलवे अफसरों की मानें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पत्र को आमतौर पर रेलवे बोर्ड विशेष तवज्जो देता है। हालांकि वर्तमान में केन्द्र में भाजपा जबकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में इस पत्र को लेकर मंत्रालय का रुख क्या रहेगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते पत्र को

में स्टॉपेज दिए जाने की मांग हो रही है। चेम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर सांसद विवेक शंकर तक इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। झांसी मंडल का भेजा एक प्रस्ताव पहले खारिज हो चुका है। सांसद के पत्र के बाद करीब 15 दिन पहले एक नया प्रस्ताव भी भेजा गया है। जिस पर भी अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। इसी बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी झांसी डीआरएम संदीप माथुर को पत्र लिखा है। जिसमें कहा है कि ग्वालियर में स्टॉपेज किए जाने से यात्री संख्या में

देखा गया तो मुंबई राजधानी का स्टॉपेज लगभग फाइनल हो सकता है।

**क्या होगा फायदा:** राजधानी दिल्ली से मुंबई का सफर करीब 16 घंटे में पूरा करती है, जबकि अन्य ट्रेनें 22-24 घंटे तक लेती हैं। ऐसे में यदि ट्रेन का स्टॉपेज ग्वालियर में होता है तो मुंबई का सफर कम समय में पूरा हो सकेगा।

**मुख्यमंत्री कमलनाथ का** राजधानी को लेकर पत्र हमें मिला है। हालांकि हम पहले ही प्रस्ताव भेज चुके हैं। सीएम के पत्र को भी रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है।

**जितेन्द्र कुमार,** सीनियर डीसीएम झांसी मंडल बढ़ोत्तरी होगी। क्योंकि शहर से काफी लोगों की व्यापारिक सिलसिले में दिल्ली मुंबई आवाजाही रहती है। मुख्यमंत्री के पत्र को रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। अब मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड के अफसर इस मामले में फाइनल निर्णय लेंगे।